stress alone. The main reason behind this — it may be one of the reasons — is the caste discrimination among the students. Therefore, I would like to know from our hon. HRD Minister what steps have been taken by the Government of India, especially the Ministry, to ensure that caste discrimination does not take place hereafter in the IITs, and the incidents of suicide is prevented henceforth in these institutions.

श्री प्रकाश जावडेकरः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं suicide के मुद्दे पर आने से पहले एक अच्छी खबर है, जिसे हाउस को बताना चाहता हूं कि IITs में पहले एक दूसरा gender discrimination था, उसमें यह होता था कि लड़कियां कम आती थीं, छात्राओं की संख्या कम होती थी, वे केवल आठ परसेंट होती थीं। हमने दो साल पहले निर्णय किया कि लड़कियों की संख्या बढ़ानी है और इसके लिए supernumerary ज्यादा सीटें तैयार की हैं। उसके कारण पिछले साल आठ परसेंट से साढ़े नौ परसेंट तक लड़कियां आईं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस साल supernumerary quota से, 840 more girls have got admission in the IITs. Now, the percentage has increased form 9 per cent to 15 per cent. We want to make it 20 per cent as soon as possible. छात्राओं को भी सर्वाधिक संख्या में इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। यह भी एक discrimination है, इसलिए मैंने पहले इसके बारे में बताया है।

जहां तक suicide का प्रश्न है, अगर एक भी suicide की घटना कहीं पर भी होती है, तो वह गलत है और वह नहीं होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस तरह की घटना IITs में हो या किसी भी संस्थान में हो, वह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक proactively काम किया है, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी IITs को एक विशेष उपाय करने के लिए कहा है। उनको एक 12 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है। एक तो induction course बढ़ा है। यह induction course पहले एक-दो दिन का होता था, उसके बजाय यह छह दिन या बारह दिन का हो, दो सप्ताह का हो, जिसमें स्टूडेंट्स acclimatize होते हैं, क्योंकि विभिन्न समुदायों से, विभिन्न background से, विभिन्न geographies से स्टूडेंट्स आते हैं। उसके एक साथ रहने के लिए induction course शुरू किया है। दूसरा, जो स्टूडेंट अलग होता जाता है, अकेला-अकेला रहने लगता है, उसी में suicidal tendency होती है, तो इसकी निगरानी करने के लिए एक टीचर्स का mentoring, एक local parenting और एक counselling centre है, जो continuous काम करता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो he can talk to them. ये बहुत सारे उपाय हैं। इनको मैं आपको सर्कुलेट भी करूंगा। We have sent 15 proactive measures to be taken so that we do not have unfortunate incidents of suicide in future. ...*(Interruptions)*...

Revival plan for loss making CPSEs

*170.SHRT P. BHATTACHARYA: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES and PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether Government has formulated any revival/restructuring plan for loss making Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and if so, what action has been taken by Government in this regard; and

(b) the number of sick PSUs revived, till date?

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ANANT GEETE): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Central Public Sector Enterprises (CPSEs) function under the administrative control of concerned Ministries/Departments and all matters relating to CPSEs including revival/ restructuring are dealt by the concerned administrative Ministry/ Department on a case-to-case basis.

Department of Public Enterprises (DPE) has issued guidelines on 29.10.2015 on revival/restructuring of CPSEs. As per these guidelines, the concerned administrative Ministries/Departments are responsible for monitoring the performance of CPSEs functioning under them and for taking timely redressal measures for revival/ restructuring/ disinvestment/closure of sick/loss making CPSEs in consultation with stakeholders and after obtaining the approval of competent authority, implement the plans.

As per the available information in DPE, the Government has approved on 21.5.2015 financial restructuring of Brahmaputra Valley Fertilizer Corpn. Ltd. (BVFCL) and setting up of a new brown field Ammonia-Urea complex at Namrup through Joint Venture. Government has also approved on 25.5.2016 the financial restructuring of Hindustan Steelwork Construction Ltd. and its takeover by NBCC (India) Ltd. Further, Government has sanctioned 2nd financial restructuring to Konkan Railway Corporation Ltd. on 15.12.2017 to improve the networth of the Company.

SHRI P. BHATTACHARYA: Madam, in the reply, it is mentioned that the Department of Public Enterprises (DPE) has issued guidelines on 29.10.2015 regarding revival/restructuring of CPSEs. Please explain what guidelines have been issued for the revival of sick industries on a case-to-case basis. You have said that on a case-to-case basis, you are trying to revive the sick industries. Madam, in West Bengal, a large number of industries are sick and many of the industries are also viable. If there is some technical arrangement, then, all these sick industries will become viable. I would like to know from the hon. Minister what the revival package is. Kindly explain this to us.

श्री अनंत गीतेः उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया है, उसके संबंध में, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से सरकार का कोई प्लान नहीं है, किंतु जो लोक उद्यम विभाग है, इस लोक उद्यम विभाग के द्वारा सारे विभागों को दिशा-निर्देश गए हैं। महोदय, जितने भी लोक उद्यम

हैं, वे भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के तहत आते हैं और यह अधिकतर उन मंत्रालयों का है कि वे case-to-case study कर के यदि कोई CPSE revival के लिए अनुकूल है, तो इस प्रकार के प्रयास उस मंत्रालय द्वारा किए जाएं। अन्त में revival का package Cabinet में approve होता है, लेकिन proposal उस मंत्रालय से आने की आवश्यकता है।

SHRI P. BHATTACHARYA: My second supplementary is, with these guidelines, how many sick industries, up till now, reopened and functioning properly? That means, you are saying that you have already ordered for a Committee or for some arrangement through which you can revive the sick industries. If it is so, then kindly tell me exactly how many industries reopened and functioning properly and how many workers are employed after the revival. In West Bengal, a large number of sick industries are there. Some of them would be viable if proper attention is given by the Government or the Government use some technical organization and not the guidelines that you have mentioned. Your guidelines have been given by the Joint Secretaries and Secretaries. I am not talking about the ...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): कृपया आप अपना सवाल सीधे पूछें, क्योंकि और भी प्रश्न हैं।

SHRI P. BHATTACHARYA: Madam, it is very important because what they are writing in the file, technically, exactly, it is something different. That is why I am saying

कि technical organization को यूज़ किया कि नहीं।

श्री अनंत गीते: उपसभाध्यक्ष महोदया, चूंकि माननीय सदस्य पश्चिमी बंगाल से हैं, इसलिए पश्चिमी बंगाल के संदर्भ में मेरे पास जो जानकारी है और वहां पर जो हमारे लोक उद्यम हैं, मैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा, लेकिन शुरू में जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा, वह यह कि सारे उपक्रम अलग-अलग मंत्रालयों के तहत हैं और उन सारे मंत्रालयों से जानकारी मंगाई जा रही है। उसके तहत जो पश्चिमी बंगाल से जुड़े CPSEs हैं, जो सारे लोक उद्यम हैं, मैं उनकी जानकारी दूंगा। वहां जो लोक उद्यम घाटे में हैं, उनकी जानकारी दूंगा और जो लाभ में चल रहे हैं, उनकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। उनमें Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited है। उसके disinvestment का process शुरू हुआ है। एक Bridge and Roof Company है। यह कंपनी लाभ में है, लेकिन फिर भी उसके disinvestment का process शुरू है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. BHATTACHARYA: Burn Standard Company.

श्री अनंत गीते: उसका भी जवाब देता हूं। Hindustan Cable जो बन्द हुई थी, उसे बन्द करने का निर्णय किया है और उसका closure हो चुका है। Burn Standard Company Limited है, उसे भी

सरकार ने बन्द करने का निर्णय किया है। Central Island jal Parivahan Corporation है, उसे भी सरकार ने बन्द करने का निर्णय किया है। Hooghly Printing Press है, उसे भी सरकार ने बन्द करने का निर्णय किया है। Hindustan Steelworks Construction Limited है, जिसे NBCC द्वारा acquire करने का provision किया गया है। पश्चिम बंगाल से related जो उद्योग हैं, उनकी जानकारी मैंने यहां माननीय सदस्य को दी है ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. BHATTACHARYA: You are saying all the industries are closed. But you are not saying that these are the industries that you are going to open. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): ठीक है। आपने अपना सवाल पूछ लिया। ...(**व्यवधान**)... श्री अमर सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री अमर सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मार्फत जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक उपक्रम बहुत ज्यादा घाटे में हैं, लेकिन मैं सभी उपक्रमों की बात न कर के, माननीय मंत्री जी से सिर्फ एयर इंडिया के बारे में जानना चाहता हूं कि जो एयर इंडिया महाराजा हुआ करता था, आज उसकी महाराजा की स्थिति बद से बदतर हो गई है और किसी पर आरोप लगाए बगैर मैं कहना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र की कई कंपनियों को मुनाफे वाला रूट देकर एयर इंडिया को क्रमशः और शनैः शनैः बीमार किया गया है। इस बीमार एयर इंडिया के उद्धार का कोई उपक्रम हुआ है या नहीं? यह महाराजा के सिर की पगड़ी की कलगी फिर निखरेगी या इसी तरह से रसातल में पड़ी रहेगी?

श्री अनंत गीते: उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह एयर इंडिया से related है और इसके लिए लग से Civil Aviation Minister है। Civil Aviation Ministry एयर इंडिया को देखती है। इसलिए अच्छा होगा यदि Civil Aviation Ministry से अलग से इसके बारे में प्रश्न किया जाए, तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी अथवा यदि आप आदेश दें, तो मैं उनको इसके बारे में जानकारी दिलवा दूंगा।

श्री अमर सिंह: मैडम, यह Public Sector Enterprise है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): ठीक है। सुश्री दोला सेन।

MS. DOLA SEN: Madam Vice-Chairman, as mentioned by the hon. Minister, many important, well-known and traditional industries, of which many are profitable too, like Bridge and Roof, Burn Standard, Hindustan Copper Limited, Hindustan Cables Limited, Alloy Steel Plant, Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Government of India Press, etc., are either being closed or disinvested by the Central Government. My humble question to the hon. Minister is whether NITI Aayog's recommendation of reducing the Central Government's stake in non-strategic companies to below 50 per cent has already been accepted by the Central Government.

श्री अनंत गीतेः उपसभाध्यक्ष जी, नीति आयोग द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं, उनको हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। जिन सार्वजनिक उद्यमों की स्थिति बहुत ही खराब है, जिनको बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं है, इस प्रकार के जो लोक उद्यम हैं, हम उन्हीं को बन्द करते हैं और जो लोक उद्यम चल सकते हैं, उनको चलाने का प्रयास किया जाता है।

श्री समीर उरांवः माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो बन्द पड़ा देश का पहला सिंदरी उर्वरक कारखाना था, उसको सरकार ने चालू किया है, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां झारखंड में केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीनस्थ HEC स्थापित है। वहां हजारों लोगों का जीवन HEC पर निर्भर है। आज HEC घाटे में चल रहा है और रुग्णावस्था में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको पुनरुद्धार और पुनर्संरचना के आधार पर आगे व्यवस्थित रूप से चलाना चाहती है।

श्री अनंत गीतेः उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने HEC के बारे में जो जानकारी दी है, वह सत्य है, वास्तविकता है। अब HEC को Atomic Energy Department takeover करना चाहता है। Atomic Energy Department से इस प्रकार का प्रस्ताव आया हुआ है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यदि Atomic Energy Department इसको takeover करता है, तो कम से कम वहां के लोगों के रोजगार निश्चित रूप से बचेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)ः प्रश्न संख्या 171. माननीय सदस्य अनुपस्थित। क्या इसके ऊपर कोई माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? श्री रामकुमार वर्मा।

*171. *[The Questioner was absent]*

Scheme for welfare of Scheduled Castes

*171.SHRI VINAY DINU TENDULKAR: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government has issued any guidelines for proper implementation of its various schemes for the welfare of Scheduled Castes (SCs) and if so, the details thereof;

(b) the details of monitoring mechanism and measures taken to ensure proper/ effective implementation of the schemes by various State Governments;

(c) whether a large number of people belonging to SC category are living below poverty line and do not possess any assets;